भारत जापान सम्बन्ध : दोस्ती के नए आयाम

India-Japan Relations: New Dimensions of Friendship

Paper Submission: 10/07/2021, Date of Acceptance: 25/07/2021, Date of Publication: 26/07/2021

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र भारत जापान सम्बन्धो के नए आयाम स्थापित करने वाले विभिन्न कारको का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, इस शोधपत्र में मुख्यतौर पर सामरिक, आर्थिक आयाम, आर्थिक सहयोग, जापानी सहायता, भारत जापान संबंधो का भविष्य तथा क्वाड जैसे सम्बन्धो की चर्चा करने की कोशिश की गयी है ।

An attempt has been made to analyze the various factors that establish new dimensions of Indo-Japan relations, in this paper, mainly strategic, economic dimensions, economic cooperation, Japanese aid, future of Indo-Japan relations and discussion of relations like Quad. has been tried to do

कुमेर सिंह गुर्जर
रिसर्च स्कॉलर
राजनीति विज्ञान विभाग,
यूनिवर्सिटी ऑफ़ राजस्थान
जयपुर, राजस्थान, भारत

श्याम मोहन अग्रवाल
एसोसिएट प्रोफेसर
यूनिवर्सिटी ऑफ़ राजस्थान
जयपुर, राजस्थान, भारत

मुख्य शब्द : भारत, जापान, क्वाड, न्यू इण्डिया।
India, Japan, Quad, New India.

प्रस्तावना

भारत जापान सम्बन्धो का एशिया की राजनीती ,विभिन्न देशो की उभरती अर्थव्यवस्था में महत्त्व पूर्ण स्थान है मुंबई बुलेट ट्रेन इसका बड़ा प्रमाण है । दोनों ही देश अपने द्विपक्षीय संबंधो को लेकर गंभीर है । भारत जापान संबन्धो का इतिहास काफी पुराना है । रवीन्द्रनाथ टैगोर और रास बिहारी बॉस की जापान यात्रा काफी महत्वपूर्ण थी ।

अध्ययन का उददेश्य

भारत जापान संबंध को मधुर बनाना है। भारत जापान एशिया के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप मे उभरे। सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक आयामों का बहुआयामी अध्ययन करना है।

भारत जापान द्विपक्षीय सहयोग

1. भारत जापान एसोसिशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई थी और वर्त्तमान में यह जापान में सबसे पुराना अन्तराष्ट्रीय मैत्री निकाय है ।
2. भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और इसी वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से द्विपक्षीय संबंधो को नई मजबूती प्रदान की गई ।
3. वर्तमान में भारत और जापान के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर की 2 + 2 बैठकों का आयोजन किया जाता है ।
4. जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऔपरेशन [JBIC] द्वारा किये गए एक सर्वे के अनुसार, अधिकांश जापानी विनिर्माण कंपनियों ने भारत को निवेश के लिए पहले या दुसरे स्थान पर रखा ।
5. वित्तीय वर्ष 2018 -19 में जापानी कम्पनियों द्वारा भारत में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.965 बिलियन अम्रिकी डालर तक पहुँच गया था । साथ ही जापान में भारत का निवेश लगभग 1 बिलियन तक पहुँच गया हैं ।
6. वर्ष 1958 से ही जापान द्वारा भारत को ऋण और अनुदान माध्यम से आर्थिक सहयोग देता रहा है, वितीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओ के लिए जापान द्वारा भारत को लगभग266बिलियन अमरीकी डालर ऋण उपलब्ध कराया गया ।

भारत में जापानी ओडीए

जापानी अधिकारिक विकास सहायता [ओडीए] भारत जापान आर्थिक संबंधो का एक और महत्वपूर्ण पहलु है। विकासशील देशो की सहायता करने के उद्देश्य से ओडीए की शुरुआत जापान ने कोलम्बो योजना पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 1954 में आरम्भ की थी । जापान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अनुदान देने वाला देश है । पिछले 30 वर्षो में जापान ने ओडीए के माध्यम से लगभग 200 अरब डालर से भी अधिक विकास सहायता प्रदान की है । और भारत 1958 में जापानी ओडीए प्राप्त करने वाला पहला देश था और 2003 -04 में भारत चीन को पीछे छोडकर जापानी ओडीए प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर भी उभरा है ।

जापान लम्बे समय से सक्रिय रूप से ओडीए के माध्यम से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। जापान ओडीए के माध्यम से भारत में कई मकसद की पूर्ति कर रहा है प्रथम ओडीए भारत –जापान सामरिक और वैश्विक साझेदारी के अनुसार भारत –जापान सम्बन्धो को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। दूसरा भारत के टिकाऊ विकास में ही एशिया का विकास शामिल है जो जापान की शांति और सुरक्षा के लिए जरुरी है। तीसरा ओडीए भारत के बुनियादी ढान्चे सहित भारत में निवेश पर्यावरण में सुधार भारत के सतत विकास और गरीबी में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में एक महत्वपूर्ण देश है और अंतिम में भारत आर्थिक उदारीकरण के प्रयासों सहित बाजार अर्थव्यवस्था के विकास को बढावा दे रहा है। वर्तमान में भारत में जापान लगभग 66 बुनियादी ढांचा परियोजनाओ को ओडीए प्रदान कर रहा है जिसमे सबसे प्रमुख परियोजनाए दिल्ली मुम्बई औधौगिक कोरिडोर ,समर्पित फरेट कोरिडोर और दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है।

उपर्युक्त परियोजनाओ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाए जो जापान द्वारा आर्थिक रूप और तकनीकी रूप से समर्थित जैसे चेन्नई मेट्रो परियोजना, दिल्ली मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट, गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना ,केरल जल आपूर्ति परियोजना, रांगाली सिंचाई परियोजना, सिक्किम जैव विविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना, हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण परियोजना, दिल्ली जल आपूर्ति सुधार परियोजना आदि कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट है।

भारत जापान का साझा द्रष्टि पत्र

भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28-29 अक्तुम्बर 2018 को जापान का दौरा किया इस दौरान वह जापान के अपने समकक्ष श्री शिंजो आबे से मिले । इस यात्रा के दौरान दोनों देशो के बीच पारस्परिक सम्बन्धो के विकास की अद्वितीय सम्भावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो ने पिछले चार वर्षो में हासिल की गई उपलब्धियों की समीक्षा की और भारत –जापान सम्बन्धो के भविष्य के लिए निम्नलिखित साझे द्रष्टिकोण को सामने रखा : - वैश्विक कार्रवाई के लिए भागीदारी

1. दोनों प्रधानमंत्रियों ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने बढते सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अपने संबंधित प्राधिकारियों के बीच सहयोग ढांचे का उपयोग करते हुए प्रदूषण नियंत्रण, टिकाऊ जैव विविधता प्रबंधन, रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रो में पर्यावरणीय साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताया। सन्युक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अपनाए गए पेरिस समझोते के अनुरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समेकित वैश्विक कार्यवाई की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए , दोनों देशो ने इस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अपने विचार साझा किए । साथ ही पेरिस समझोते के कार्यान्वयन के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और ज्वाइंट क्रेडीटिंग मैकेनिज्म की स्थापना के लिए और परामर्श में तेजी लाने के वास्ते अपनी प्रतिबधता दौहराई।

2. दोनों देशो ने परमाणु और नवीनीकरण सहीत उर्जा के टिकाऊ और स्वच्छ रूपों पर सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जिसमे परमाणु और नवीनीकरण सहित हाइड्रोजन आधारित उर्जा में सहयोग के लिए संभावनाओ का पता लगाना शामिल है। जबकि स्वच्छ कोयला प्रोधौकिकी , पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस परियोजना और एनएलजी आपूर्ति श्रंखला के उपयोग में सहयोग के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए और भारत जापान एनर्जी ट्रांजिशन कोपरेशन प्लान का स्वागत किया । भारत और जापान उर्जा दक्षता और संरक्षण उर्जा भंडारण के साथ साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों सहीत पर्यावरण अनुकूल वाहनों के निर्माण में सहयोग करेंगे । दोनों नेताओ ने असैनिक परमाणु सहयोग पर भारत जापान परामर्श की प्रगति का स्वागत किया । भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया क्योकि यह सौर उर्जा की स्वच्छता , किफायती और टिकाऊ उर्जा विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करेगा ।

3. दोनों नेताओ ने आपदा जोखिम में कमी ,सहयोगी कार्यशालाओ के साथ साथ विभिन्न मंचो में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय रूप से सहयोग की प्रगति की संतुष्टि के साथ समीक्षा की । उन्होंने प्रारम्भिक चेतावनी तंत्र , जल संसाधन प्रबंधन ,अंतरिक्ष –आधारित प्रौद्योगिकी और आपदा से निपटने के लिए आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रो की वजह से आपदा जोखिम में कमी को लेकर 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्त्व को स्वीकार किया ।

4. दोनों नेताओ ने नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और WTO को सुधारने के लिए तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही WTO कार्यप्रणाली,निरंतर विकास और विकास को प्राप्त करने के लिए मुक्त निष्पक्ष और खुले व्यापार को बढावा देने पर जोर दिया। उन्होंने स्वंय को सभी अनुचित व्यापार प्रथाओ सहित संरक्षणवाद का विरोध करने की सिफारिश की और व्यापारिक गतिविधियों को विक्रत करने वाले कदमो को हटाने की आवश्यकता को रेखांकित किया । दोनों देशो ने मुक्त और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र के पूर्ण लाभ को साकार करने को लेकर एक उच्च गुणवत्ता वाले ,व्यापक और संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझोते के लिए बातचीत के शुरूआती निष्कर्ष के रणनीतिक महत्त्व की पुनः पुष्टि की ।

5. दोनों प्रधानमंत्रियो ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचो तथा संस्थानों में परामर्श एवं समन्वय बढाने के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने सतत विकास, आर्थिक स्थिरता ,भोजन ,जल सुरक्षा ,पर्यावरण संरक्षण,आपदा शमन, आतंकवाद ,साइबर सुरक्षा ,स्वच्छ उर्जा और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास को बढावा देने के लेकर अपने समय की जरूरतों और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से रेखांकित करने के लिए अपनी प्रतिबधता जाहिर की। दोनों प्रधानमंत्रियो ने फिर से इसकी पुष्टि की कि दोनों देशो के बीच संबंधो को हाल के वर्षो में ठोस उद्देश्यों को हासिल किया है। उन्होंने आज भारत –जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी की परिपक्वता में अपने पारस्परिक विश्वास और गहरे विश्वास को रेखांकित किया। साथ ही दोनों देशो के सुरक्षित भविष्य के लिए वचन दिया क्योकि वे संयुक्त रूप से एक अधिक सुरक्षित ,शांतिपूर्ण दुनिया और समर्द्ध क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे है ।

विशेष रूप से 21 शताब्दी की समकालीन वास्तविकताओ को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के व्यापक सुधार को और अधिक वैध ,प्रभावी और प्रतिनिधिक बनाने के लिए भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र में त्वरित और सार्थक सुधार चाहते है ।

शांति के लिए साझेदारी

1.वर्ष 2008 में सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद दोनों प्रधानमंत्रियो ने साझा सुरक्षा के प्रति संयुक्त प्रयासों को बदावा देने के लिए पिछले दशक में

प्रगति को लेकर बड़ी संतुष्टि जाहिर की । दोनों नेताओ ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी इच्छा है कि द्विपक्षीय और रक्षा सहयोग को गहरा किया जाए। वार्षिक रखा मंत्रीय स्तरीय संवाद ,रक्षा नीति संवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संवाद ,स्टाफ लेवल डायलोग के अलावा फारेन एंड डिफेन्स मिनिस्ट्रियल डायलाग 2+2 की स्थापना की जाए । दोनों नेताओ ने तिन सेवाओ में से प्रत्येक के बीच संयुक्त अभ्यास और अधिग्रहण और क्रास सर्विसिंग एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू करने का स्वागत किया जिससे द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे ।

2. दोनों नेताओ ने समुद्री सुरक्षा सहयोग में महत्त्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया जैसा कि द्विपक्षीय नौ सेना अभ्यास की उच्च आवर्ती और मालाबार अभ्यास में देखा गया है साथ साथ ही लंबे समय तक संवाद और कोस्ट गार्ड को लेकर प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है । इस बात को रेखांकित करते हुए की भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री प्रभाव क्षेत्र जागरूकता का विस्तार करने में उन्नत आदान प्रदान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान देता है दोनों नेताओ ने भारतीय नौ सेना और जापान समुद्री स्व रक्षा बल के बीच सहयोग बढाने को लिए इम्पलिमेंटिंग अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया ।

3. रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी पर भारत और जापान के बीच सहयोग सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रो के बीच संयुक्त प्रयासों के माध्यम से तकनिकी क्षमता और औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए अत्यधिक अवसर सर्जित करने की क्षमता रखता है । इसके मद्देनजर दोनों नेताओ ने भारतीय और जापानी रक्षा उद्योगों को बढावा देने के लिए और मानव रहित जमीनी वाहन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में सहकारी अनुसन्धान के शुरू होने का स्वागत किया । दोनों देश यूएस 2 एम्फिबियन विमान पर सहयोग के संबंध में अपना प्रयास जारी रखेंगे ।

4. दोनों प्रधानमंत्रियो ने आतंकवाद के बढते खतरे और इसकी सार्वभौमिक पंहुच की कड़े शब्दों में निंदा की उन्होंने सभी देशो से आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगाहो और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने ,आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्त पोषण चैनलों को बाधित करने और आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए काम करने का आवाहन किया उन्होंने सभी देशो को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य तरीके से अन्य देशो पर आतंकवादी हमला करने के लिए नही किया जा रहा है । दोनों नेताओ ने अलकायदा ,isis, जैश ए मुहम्मद ,लश्कर ए तैयबा और उनके सहयोगी समूहों सहित आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहोग को मजबूत बनाने की उम्मीद जाहिर की । उन्होंने पाकिस्तान का आतंकवादी हमलो के जिम्मेदार अपराधियों को न्याय के कठघरे में खड़ा करने का आवाहन किया ।

भारत जापान द्विपक्षीय संबंधो का महत्त्व

1. पिछले कुछ वर्षो में भारत ने अन्य देशो का अनुसरण करने के बजाय समान विचारधारा वाले देशो के साथ द्विपक्षीय संबंधो को बढाने पर विशेष जोर दिया है ।
2. वर्ष 2014 से 2019 के बीच दोनों देशो के शीर्ष नेताओ की यात्राओं और कई महत्वपूर्ण समझोतों के माध्यम से द्विपक्षीय सम्बन्धो को नई उर्जा प्रदान की गई है ।
3. हाल के वर्षो में साझा प्रयासो के परिणाम स्वरूप जापान भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशकर्ता देश बन गया है ।
4. .हिन्द प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशो द्वारा भारत के समर्थन में अपने हित निहित हो सकते है, ऐसे में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जापान का सहयोग भारत के लिए एक बड़ी सामरिक उपलब्धि है ।
5. भारत जापान की सेनाओ के साझा सैन्य अभ्यास बहुत ही लम्बे समय से होता रहा है परन्तु अब इस सहयोग को तकनीकी रूप से आगे जाते हुए दोनों देशो के बीच निगरानी पनडुब्बियो और समुद्री निगरानी विमानों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने

जैसे प्रयासों से क्षेत्र को सुरक्षा को और अधिक सुढढ किया जा सकता है ।

क्वाड

1. चतुर्भुज सुरक्षा संवाद [QU ।D] अर्थात क्वाड भारत ,अमरीका, जापान और आस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है ।
2. यह मुक्त , खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन देशो को एक साथ लाता है ।
3. क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी हालाकि चीन के दबाव में आस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नही बढाया जा सका ।
4. शिंजो आबे द्वारा वर्ष 2012 में हिन्द महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आस्ट्रेलिया ,भारत , जापान ,और अमरीका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया ।
5. क्वाड समूह की स्थापना नवम्बर 2017 में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति [विशेषकर चीन]के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए हुई ।

न्यू इण्डिया

शिंजो आबे ने अपनी पुस्तक UTSUKUSHII KUNI E [टुवर्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री] में आशा व्यक्त की हैं कि यदि 10 वर्षो में जापान भारत के सम्बन्ध, जापान-यूएस एवं जापान चीन संबंधो से आगे बढ़ जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नही होगी ।

अतएव न्यू इण्डिया के पास यह मानने के लिए पर्याप्त वजह है कि जापान और भारत दोनों मिलकर विकास के बेहतर परिणामो के लिए प्रयासरत रहेंगे ।

निष्कर्ष

जापान विश्व के उन देशो में शामिल है जिनके साथ भारत का कोई बड़ा विवाद नही रहा है । भारत जापान सम्बन्धो के इतिहास को छठी शताब्दी में जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत के साथ जोड़ा जाता है हाल के वर्षो में दक्षिण चीन सागर में चीन की बदती आक्रामकता और हिन्द प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को देखते हुए दोनों देशो के बीच रक्षा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत और जापान के बीच सामरिक आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के लिए बड़ी क्षमता है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *वी पी दत्त [2016] इंडियाज फोरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया*
2. *खन्ना वी एन [2013] फोरेन पॉलिसी ऑफ़ इंडिया ,विकास पब्लिशिंग हॉउस नोएडा*
3. *pib.gov.*
4. *लालिमा वर्मा 2009 जापान्स आफिसियल डेवलपमेंट असिस्टेंट टू इंडिया, ए क्रिटिकल अप्रेजल इंडिया क्वाटर्ली जनरल ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स*
5. *जैन बी0 एम0 अतरर्राष्ट्रीय संबंध। राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ*
6. *अकादमी जयपुर प्रकाशन।*
7. *मिश्रा राजेश भारत की विदेश नीति, ओरियंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन दिल्ली।*